भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3453

जिसका उत्तर 01 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है ।

11 चैत्र, 1944 (शक)

डिजिटल साक्षरता

3453. श्रीमति फूलो देवी नेतम:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार, 'नव भारत के लिए नीति आयोग की रणनीति' रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 तक शत-प्रतिशत डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या हैं, और क्या एक संशोधित लक्ष्य और/अथवा समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) लिंग-वार और शहरी/ग्रामीण श्रेणी-वार विवरण सहित वर्ष 2016 से आज की तिथि तक भारत में वर्ष-वार डिजिटल साक्षरता दर कितनी है;

(घ) भारत में (ग्रामीण तथा शहरी घरों में) प्रति 100 व्यक्तियों पर इंटरनेट का उपयोग करने वालों की कुल संख्या कितनी है; और

(ड.) ऐसे शहरी और ग्रामीणी घरों का प्रतिशत कितना है जिनके पास कम्प्यूटर है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और **(ख)** : नीति आयोग की रिपोर्ट "नए भारत के लिए रणनीति @ 75" शीर्षक से अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित संकेत मिलता है कि भारत को 2022-23 तक डिजिटल डिवाइड को खत्म करने की जरूरत है। इस संबंध में यह कहा गया है कि कौशल विकास और कुशल प्रतिभा का निर्माण यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन है कि भारत की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रशिक्षित और कुशल जनशक्ति प्रदान की जाती है जिसकी उद्योग को आवश्यकता होती है। डिजिटल अपनाने में और सहायता करने के लिए मंत्रालय ने देश भर में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, 2014 से नागरिकों के लिए डिजिटल साक्षरता पर ध्यान केंद्रित किया है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने देश में डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए निम्नलिखित पहल की हैं:

i. लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ सरकार द्वारा " राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन" (एनडीएलएम) और " डिजिटल साक्षरता अभियान" (दिशा) नामक दो योजनाओं को लागू किया गया था । इन दो योजनाओं के तहत कुल 53.67 लाख लाभार्थियों को प्रमाणित किया गया ।
ii. " प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)" नामक एक योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को शामिल करके

ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता लाने के लिए मंजूरी दी थी। अब तक लगभग 5.78 करोड़ उम्मीदवारों का नामांकन किया गया है और 4.90 करोड़ को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से लगभग 3.62 करोड़ उम्मीदवारों को इस योजना के तहत प्रमाणित किया गया है ।

(ग): शिक्षा से संबंधित सामाजिक उपभोग पर जून 2015 में जारी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के 71 वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार 14 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लिए लिंग-वार विवरण, ग्रामीण और शहरी में कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता क्षेत्रों को निम्नानुसार सूचित किया गया था:

जनसंख्या का अनुपात (प्रति 1000) (उम्र 14 वर्ष और उससे अधिक) एक कंप्यूटर संचालित करने में सक्षम								
लिंग	**ग्रामीण**				**शहरी**			
	आयु समूह (वर्ष)							
	14-29	**30-45**	**46-60**	**60 और ऊपर**	**14-29**	**30-45**	**46-60**	**60 और ऊपर**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
पुरुष	227	64	22	6	536	309	209	106
महिला	135	19	5	1	438	173	87	28
व्यक्तियों	**183**	**41**	**14**	**3**	**489**	**243**	**148**	**68**

इसके अलावा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जुलाई 2017 से जून 2018 तक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 75 वें दौर के हिस्से के रूप में घरेलू सामाजिक उपभोग: शिक्षा पर एक सर्वेक्षण किया। रिपोर्ट, ग्रामीण और शहरी भारत में नीचे उल्लिखित आयु समूहों में कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति का लिंग-वार विवरण निम्नानुसार है:

व्यक्ति का आयु समूह	**%कंप्यूटर संचालित करने में सक्षम**			
	ग्रामीण		**शहरी**	
	पुरुष	**महिला**	**पुरुष**	**महिला**
15-29 वर्ष	29.4	17.6	60.6	50.9
15-59 वर्ष	16.4	8.6	44.3	31.4

(घ) : दूरसंचार विभाग (डीओटी), संचार मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 2022 को प्रकाशित "भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक" रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 30 सितंबर, 2021 में प्रति 100 जनसंख्या पर 37.67 ग्रामीण इंटरनेट ग्राहक और प्रति 100 जनसंख्या पर 104.75 शहरी इंटरनेट ग्राहक थे।

(ड.) : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) रिपोर्ट के एनएसओ 75 वें दौर के अनुसार ग्रामीण परिवारों में केवल 4.4% और शहरी परिवारों में 23.4% के पास कंप्यूटर है।

******